

# इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कहा- अभिनव वित्त मॉडल से तेज़ होगा हरित ऊर्जा का विकास



जयपुर, 28 अगस्त, 2025

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने आज जयपुर के मैरियट होटल में आयोजित द इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिज़नेस समिट में "हरित परिवर्तन - नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अभिनव विकास और वित्तपोषण मॉडल" विषय के बारे में एक पैनल चर्चा के दौरान अपने विचार साझा किए।

श्री दास ने रेखांकित किया कि भारत अपने हरित परिवर्तन के वृद्धि चरण में मजबूती के साथ प्रवेश कर चुका है, जिसमें जुलाई 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 237 गीगावाट को पार कर चुकी है और गैर-जीवाश्म स्रोत से स्थापित बिजली का 50% योगदान रहा है। वित्तीय वर्ष 25 में 60 से अधिक अतुल्य समूहों द्वारा उपयोगिता-स्तरीय निविदाएं जीतने के साथ, उन्होंने बाजार की बढ़ती गंभीरता के बारे में ध्यान दिए और जोर दिए कि वर्ष 2030 तक 485 गीगावाट के लक्ष्य को पूरी करने के लिए लगभग 50 गीगावाट की वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिसे मजबूत घरेलू विनिर्माण, समय पर ग्रिड का विस्तार और सतत निवेश के माध्यम से समर्थित किया जाएगा।

उन्होंने वैश्विक और घरेलू पूंजी प्रवाह में एक निर्णायक बदलाव के बारे में प्रकाश डाला, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अब मुख्यधारा के विकास के क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। ओवरसब्सक्राइब्ड आईपीओ, बढ़ती खुदरा भागीदारी और रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई का प्रवाह (3 वर्षों के दौरान 2.5 गुना वृद्धि) भारत की स्वच्छ ऊर्जा के बारे में कहानी, बढ़ते निवेशक के विश्वास का संकेत देते हैं।



श्री दास ने इस बात पर जोर दिया कि इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए शीघ्रता से ऋण मूल्यांकन, अनुकूलित और अभिनव वित्तपोषण मॉडल के साथ संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला का वित्तपोषण, और नीति निर्माताओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निवेशकों और उद्योग जगत के अगुओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाओं के योजना से लेकर कमीशनिंग होने तक तेज़ी से कार्य करें और भारत वर्ष 2030 तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पार करने की राह पर बना रहे।

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने माननीय मुख्यमंत्री, श्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 'राजस्थान के भविष्य को सशक्त बनाना: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निवेश और वित्तपोषण के रास्ते' के विषय पर एक परिचर्चा में भी भाग लिया, जिसमें परियोजनाओं को जोखिम मुक्त करने और राज्य भर में स्वच्छ ऊर्जा की तैनाती में तेज़ी लाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के नेतृत्व वाली रणनीतियों के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया।